

पत्रिका XPOSE

mega स्टोरी

सोमवार
30 सितंबर 2013 9

मतिष्य में रेलगाड़ी से सिंगापुर, तुर्की, रूस, कोरिया जैसे देशों का सफ़र हो सकेगा, यह सपना या मजाक नहीं, बल्कि ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क इसे संभव बना सकता है।

ऋषि कुमार सिंह

एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया मध्य एशिया और यूरोप को रेलमार्ग से जोड़ने की योजना का नाम ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क है। इसमें प्रमुख तौर पर चार कॉरिडोर होंगे, जो विभिन्न देशों को आपस में जोड़ देंगे। 10 नवंबर 2006 को इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ 1960 में की गई परिकल्पना को तैस आधार मिला है। लगभग 80,900

किमी के कुल रेलमार्ग से उन देशों को सर्वाधिक फायदा होगा, जो स्थलरुद्ध होने के नाते समुद्री यातायात की सुविधा से दूर हैं। यह अंतरराष्ट्रीय फलक पर आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को लेकर नए अवसर उपलब्ध कराएगा।

सबको जोड़ेगी ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क

10 नवंबर 2006

दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में 18 देशों ने ट्रांस एशिया रेल नेटवर्क के इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।



चारों कॉरिडोर संकेत ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क का मानचित्र।

ट्रेन से जुड़ने वाले देश और दूरी

क्षेत्र	दूरी	देश
साउथ-ईस्ट एशिया	12,600	कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीपुल्स डिमोक्रेटिक गणराज्य, मलायेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम
नॉर्थ, नॉर्थ-ईस्ट एशिया	32,500	चीन, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस फेडरेशन
सेंट्रल एशिया, ककस	13,200	अर्जेंटीना, अज़रबैजान, जातिरिया, कजाखस्तान रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान
साउथ एशिया	22,600	ईरान, तुर्की बांग्लादेश, भारत, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तुर्की
कुल	80,900	

लाम और चुनौतियां

ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए अवसर देखे जा रहे हैं। खासतौर पर वे देश, जो स्थलरुद्ध होने के नाते बंदरगाहों की सुविधा से हज़ारों किमी दूर हैं, ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था व रेल नेटवर्क बंदरगाहों से जुड़ जायगी, जो किसी भी देश के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए सबसे यातायात सघन के रूप

में महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा इसे पर्यावरण अनुकूल, चिपकावटों व गलतसेनायक यातायात के संचालन के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि इसके संचालन में विभिन्न, संकलन और व्यावहारिक स्तर की चुनौतियां हैं। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाले विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय के साथ कॉलन इंफ़ोर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास पर ध्यान देने की जरूरत है।

प्रोजेक्ट के चार प्रमुख हिस्से

ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क के लिए श्रेयसोपरी ने 'स्टेप बाय स्टेप' दृष्टिकोण अपनाया है। क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर प्रोजेक्ट को चार हिस्सों में बांटा गया है। प्रथम: नॉर्थ-ईस्ट एशिया के लिए चीन, कजाखस्तान, मंगोलिया, रियन फेडरेशन और कोरियन प्रायद्वीप रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे। दो: साउथ-ईस्ट एशिया से थाईलैंड और वियतनाम चीन का यूनान प्रांत म्यांमार, बांग्लादेश,

भारत, पाकिस्तान और ईरान के जरिए तुर्की से जुड़ेंगे। श्रीलंका भी इसका हिस्सा होगा। तीस: सार्वजनिक नेटवर्क के सहित अफ़्गानिस्तान और इंडो-चीन सार्वजनिक को जोड़ा जाएगा। चार: नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर से नार्दन यूरोप और पर्सियन खाड़ी को रियन फेडरेशन, सेंट्रल एशिया और ककस क्षेत्र के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

रेल नेटवर्क का सफ़र

1960
यूएनएडो नेटवर्क इकोनॉमिक कॉन्फ़िडेंस ऑफ़ एशिया एंड फ़ार ईस्ट (यूएनईसीएफ़ई) ने सिंगापुर से लेकर तुर्की तक 14,000 किमी दूरी की ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क का प्रस्ताव किया।

1976
यूएनईसीएफ़ई ने 22वीं बैठक में प्रोजेक्ट परदे में शामिल क्षेत्रों व बंदरगाहों को जोड़ने का प्रस्ताव। ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क का भारत एनएल का प्रयास शुरू हुआ।

1996
हालांकि विकास पर नई दिल्ली में मंत्रीस्तरीय बैठक। 1997-2006 टाइम के लिए एक्शन प्लान घोषित।

2000
यूएनईसीएफ़ई और इंटरनेशनल यूनिटन ऑफ़ रेलवे ने सहयोग व विद्येयता समझौते के लिए समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किया।

2001
रियोल (रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया) में हायागत विकास को लेकर मंत्रीस्तरीय बैठक। नई दिल्ली रीजनल एक्शन प्लान के दूसरे चरण (2002-06) पर बनी सझौती।

2002
बेलायूस, चीन, पोर्तुगल, इंटरनेशनल यूनिटन ऑफ़ रेलवे और अर्जेंटीना ऑफ़ रेलवे को-ऑपरेशन में नॉर्थ कॉरिडोर के लक्ष्य बॉयक-ट्रेन संचालन के लिए योजना तैयार की।

2003
चीन-मंगोलिया के बीच ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क के नॉर्थ कॉरिडोर पर पहली बॉयक ट्रेन का संचालन किया गया।

2004
यूएनईसीएफ़ई की 28वीं बैठक की 80वीं बैठक में रेल नेटवर्क के लिए विद्येयता की पहली बैठक आयोजित की। बैठक में हुई बैठक में मंडोय तैयार करने का काम पूरा।

2005
भारतीय रेलवे और यूएनईसीएफ़ई ने समुदाय रूप से नई दिल्ली में इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया। 2007-08 के बीच चार और देशों ने हस्ताक्षर किए।

2006
बुसान, रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया में हस्ताक्षर समझौते का आयोजन। 18 सहभागी देशों ने हस्ताक्षर किए। 2007-08 के बीच चार और देशों ने हस्ताक्षर किए।

भारत की भूमिका और हित

ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क (टीएआरएन) के तहत भारत पूर्वोत्तर राज्यों में रेल नेटवर्क विकसित कर रहा है। म्यांमार को जोड़ने वाले 118 किमी हिस्से पर नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे सर्वेक्षण कार्य कर रहा है। इससे मणिपुर की राजधानी इम्फाल को सीमावर्ती मोराह और पश्चिमी म्यांमार के तामू से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा त्रिपुरा के जवाहर नगर रेलवे स्टेशन को उत्तरी मिजोरम के कोलासिब और म्यांमार के डरलोन से जोड़ने का प्रस्ताव है।

2007
भारत ने 29 जून को इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ऑन ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क पर हस्ताक्षर किया।

नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के चीफ इंजीनियर हसलत सिंह के अनुसार, त्रिपुरा और मणिपुर के ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क से जुड़ने के बाद पूर्वोत्तर राज्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के गेटवे साबित होंगे। पूर्वोत्तर परिषद की तरफ से तैयार बिजन-2020 के तहत नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे पूर्णोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को आपस में जोड़ा जाना

है। अभी गुवाहाटी और अगरतला तक ही रेल संपर्क मौजूद है। अगले वर्ष बांग्लादेश को रेल लिंक से जोड़ने पर काम शुरू होगा। इस 15 किमी रेलवे ट्रेक के निर्माण पर भारत 252 करोड़ रुपए का खर्च करेगा, जिससे अगरतला, बांग्लादेश के पश्चिम-पूर्वी शहर अखुवह से जुड़ जाएगा। यह बिजगांव से मुंडा साहेल और राजधानी ढाका को जोड़ने वाला प्रमुख जंक्शन है। 2010 में भारत-बांग्लादेश इस पर समझौता कर चुके हैं। टीएआरएन के विकास से पूर्वोत्तर राज्यों की दूरी में कमी आ जाएगी। अभी अगरतला-कोलकाता के बीच कुल दूरी 1650 किमी है, गुवाहाटी-पश्चिम बंगाल के रास्ते नई दिल्ली-अगरतला की दूरी 2637 किमी है, जबकि बांग्लादेश के जरिए कोलकाता और अगरतला की दूरी मात्र 350 किमी रह जाती है। यह पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्री यातायात से भी जोड़ने में मददगार होगा।



